भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1935
उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

स्कूलों में डिजिटल अधिगम

1935 **श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:**
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने स्कूलों में डिजिटल अधिगम को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए क्या कार्यप्रणाली अपनाई गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का भाग है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन हैं। देश भर के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा के तहत पीएम ईविद्या, दीक्षा और स्वयम् जैसी आईसीटी और डिजिटल पहलों को क्रियान्वित करता है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकता के अनुसार आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

17 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो देश भर में शिक्षा के लिए मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटकों को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में भी अनुकूलित किया है और इसमें 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा) सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर कोड वाली सक्रिय पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए

गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकायों (एबी) ने बहुभाषावाद को सक्षम करने के लिए मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। हितधारकों के पास दीक्षा पर 836 से अधिक वर्चुअल लैब तक भी पहुंच है जो उन्हें वास्तविक दुनिया के प्रयोगशाला वातावरण के अनुकरण में मदद करती हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह की पहुँच में सहायता करता है, जिससे शिक्षार्थी सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट के बिना भी अधिगम जारी रख सकते हैं।

भारत सरकार ने बजट 2025 में बीएसएनएल द्वारा चरणबद्ध तरीके से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की व्यवस्था की घोषणा की है।

(ग): स्कूल शिक्षा के मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः ग्रेड 3, 6 और 9) के अंत में छात्रों के बीच दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र-परख, एनसीईआरटी द्वारा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) किया गया था। देश भर में 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक छात्रों और 2.70 लाख शिक्षकों और स्कूल अग्रणियों ने मूल्यांकन में भाग लिया।

छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि की व्यापक समझ हासिल करने और मूल्यांकन के निष्कर्षों की अधिक व्यापक व्याख्या को सक्षम करने के लिए, सर्वेक्षण के दौरान कई तरह के संदर्भ-संबंधी कारकों के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई। इन कारकों में घर और स्कूल में डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट की सुविधा शामिल थी।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्ट में, चरण विशिष्ट दक्षताओं और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले संदर्भ-संबंधी कारकों की उपलब्धि संबंधी अनुभव, मूल्यांकन के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक समर्पित डैशबोर्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en. पर उपलब्ध है।

******